नईदुनिया

करीलाधाम के विकास के लिए एक करोड़ की राशि करेंगे स्वीकृत

■ मुख्यमंत्री ने खेली फूलों की होली ■ माँ जानकी के दर्शन कर की सभी के सुख-समृद्धि की कामना

भोपाल (काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार भगवान श्रीराम के प्रदेश में विभिन्न आगमन स्थलों के संरक्षण और उन्नयन का कार्य कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण लीला-स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने के लिये श्रीकृष्ण पाथेय योजना को क्रियान्वित करने का काम भी किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि करीला धाम में भी श्रृद्धालुओं को आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिये एक करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की जायेगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को अशोकनगर के करीला धाम में माँ जानकी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने रंगपंचमी

के पावन पर्व पर श्रृद्धालुओं के साथ फूलों की होली भी खेली।

डॉ. यादव ने कहा कि करीला धाम में श्रृद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। मेले की व्यवस्थाओं को और अधिक पुख्ता किया जायेगा, यह प्रयास किया जायेगा कि करीला धाम मेला राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाये। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में करीला धाम में आने जाने वाले मार्गों पर श्रृद्धालुओं के लिए छाया की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का संबंध चंदेरी से होने के कारण यहां की गढ़ी को भव्य बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीराम, माता जानकी और रघुकुल के आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके द्वारा स्थापित किये गये आदर्श संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि करीला धाम की दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा ऐसी है कि एक बार जो यहां आता है, वह स्वयं को बार-बार आने से रोक नहीं पाता। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राई नृत्य का जिक्र करते हुए कहा कि जब भगवान श्रीराम के घर में लव-कुश का जन्म हुआ होगा, तब इसे रघुराई नृत्य कहा जाता रहा होगा।

सच्चे अर्थों में रोज़ होली और दिवाली

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण का नाम लिया जाता है, तो रोम-रोम में आनंद छा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की भागीदारी और आस्था ही इस तरह के भव्य आयोजनों को सफल बनाती है। डॉ यादव ने सभी प्रदेशवासियों को रंगपंचमी की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुखद और समृद्ध भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला,पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजेन्द्र सिंह यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव और पूर्व सांसद डॉ. केपी यादव ने भी संबोधित किया। बीना विधायक निर्मला सप्रे, आलोक तिवारी, सरपंच ग्राम पंचायत जसैया श्रीमती सुनीता यादव, अध्यक्ष करीला मंदिर ट्रस्ट महेन्द्र यादव, आयुक्त ग्वालियर संभाग मनोज खत्री, आईजी अरविन्द सक्सेना, कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन उपस्थित थे।

खास खबरें...

मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नेशनल सेमिनार ऑन हैप्पीनेस आज

भोपाल। राज्य आनंद संस्थान द्वारा 20 मार्च को प्रात: 10 बजे से नेशनल सेमिनार ऑन हैप्पीनेस का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सेमिनार में सायं 5:45 बजे शामिल होंगे। सेमिनार में देश के विभिन्न प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिनार का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय आनंद दिवस पर किया जा रहा है, जिसका समापन 21 मार्च को होगा। संस्थान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आशीष कुमार ने बताया कि दो दिवसीय सेमिनार के दौरान आनंद के विभिन्न आयामों पर व्याख्यान एवं परिचर्चा सत्र आयोजित किये गये हैं। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में आनंद गतिविधियों से जुड़े संगठन और स्वयंसेवी सम्मिलित हो रहे है। सेमिनार में भारतीयता में आनंद के आयाम, दैनिक जीवन में निरंतर आनंद, भारतीय संस्कृति एवं आनंद, एक आनंदित समाज के लिये वैज्ञानिक अंर्तदृष्टि का समीकरण विषय पर पहले दिन प्रो. रजनीश अरोड़ा, स्वामी समर्पणानंद, डॉ. एन रविचंद्रन, रिटायर्ड आईपीएस मुकेश जैन व्याख्यान होंगे। बच्चों में मानवीय मूल, आंतरिक आनंद की अनुभूति विषय पर भी परिचर्चा सत्र आयोजित किये जायेंगे।

इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर के निर्णय पर किसानों ने माना आभार

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बुधवार को इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर क्षेत्र के किसानों ने विकसित भूमि का 60 प्रतिशत हिस्सा आवंटित करने के राज्य सरकार के निर्णय के लिये आभार व्यक्त किया। किसानों ने डॉ. यादव से बुधवार को इंदौर एयरपोर्ट पर मिलकर आभार जताया। एयरपोर्ट पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। किसानों ने सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय के लिये मुख्यमंत्री का सम्मान करना चाहा, जिसे मुख्यमंत्री ने इंदौर गेर में हुए हादसे के कारण विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर में सरकार द्वारा कुल विकसित भूमि का 60 प्रतिशत हिस्सा किसानों को आवंटित करने के निर्णय से आस-पास के गांवों के ग्रामीण लाभान्वित होंगे। प्रस्तावित योजना में कोडियाबर्डी, नैनोद, रिंजलाय, बिसनावदा, नावदा पंथ, श्रीराम तलावली, सिन्दोड़ा, सिन्दोड़ी, शिवखेड़ा, नरलाय, मोकलाय, डेहरी, सोनवाय, भैंसलाय, बागोदा, टीही और धन्नड़ जैसे गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें कुल 1290.74 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाएगा, जिसमें से किसानों को मुआवजे के बदले विकसित भूमि का 60 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।

अपराधियों को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाने राज्य सरकार प्रतिबद्ध

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अपराधियों को सजा दिलाकर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। राजधानी के शाहजहांबाद में सितम्बर 2024 में हुई 5 साल की बच्ची के अपहरण-दुष्कर्म और हत्या के प्रकरण में, अपराधी को 3 प्रकरणों के आधार पर 3 बार फांसी की सजा मिली है, जो भविष्य में अपराध करने वालों के लिए मिसाल बनेगी। राज्य सरकार किसी भी अपराधी को छोड़ने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री प्रकरण में हुई त्वरित कार्रवाई और माननीय न्यायालय द्वारा दिए निर्णय के संबंध में विचार व्यक्त कर रहे थे। डॉ. यादव ने कहा कि जघन्य अपराध की व्यापक विवेचना के लिए राज्य सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था। प्रकरण में न केवल अपराधी को पकड़ा गया अपितु तत्परतापूर्वक चालान पेश करवाया गया। इस प्रकरण की सुनवाई भी त्वरित रूप से हुई। माननीय न्यायाधीश ने जो फैसला दिया है उससे यह फैसला मिसाल बना है। यह फांसी की सजा सभी अपराधियों को सबक है। मुख्यमंत्री ने प्रकरण में तत्परतापूर्वक कार्रवाई के लिए प्रशासन और पुलिस को बधाई दी है। उन्होंने न्यायालय द्वारा कम समय में संवेदनशीलता के साथ लिए गए निर्णय पर संतोष व्यक्त किया है।

भारत की बेटी सुनीता की सकुशल वापसी से रंगपंचमी का आनंद और अधिक बढ़ गया

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत की बहादुर बेटी, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एवं अन्य साथियों को अपनी 9 महीने की लंबी यात्रा पूर्ण कर सकुशल पृथ्वी पर लौटने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण हैं, सुनीता विलियम्स की यह यात्रा विज्ञान के साथ-साथ नारी शक्ति और धैर्य की विजय है। यह अभूतपूर्व कीर्तिमान अंतरिक्ष जगत के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। भावी पीढ़ियों और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में शोध के लिए उनकी यह यात्रा स्वर्णिम मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि भारत की बेटी सुनीता के सकुशल लौटने से रंगपंचमी का आनंद और अधिक बढ़ गया है। डॉ. यादव ने मीडिया को जारी संदेश में यह भाव व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी रंगपंचमी की बधाई

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशावासियों को रंग पंचमी की मंगलकामनाएं दी हैं। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि रंगपंचमी, आनंद और उत्साह का पावन पर्व है। उन्होंने ईश्वर से कामना की कि हमारे जीवन के सारे कलुषित रंग निकलें, चटख बसंती रंग के साथ हम अपने जीवन की नई यात्रा आरंभ करें। डॉ. यादव ने कहा कि रंगों का ये उल्लास सभी के जीवन में खुशियां भर दे। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रेम-सौहार्द्र और उमंग से भरा यह पर्व सबके जीवन में उल्लास और सुख-समृद्धि लेकर आए। मुख्यमंत्री ने रंगपंचमी के अवसर पर अशोकनगर जिले के करीला धाम और इन्दौर व उज्जैन की प्रसिद्ध गेर में शामिल हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री आज नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का करेंगे लोकार्पण

2489 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की है परियोजना

भोपाल (काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 20 मार्च को उज्जैन जिले के तराना में 2,489 करोड़ 65 लाख रुपए लागत की नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन करेंगे।

परियोजना से क्षेत्र के कुल 100 ग्रामों की 30 हजार 218 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे उज्जैन जिले की दो तहसीलों (तराना, घट्टिया) के कुल 83 ग्रामों की 27,490 हेक्टेयर भूमि और शाजापुर जिले की एक तहसील (शाजापुर) विधानसभा क्षेत्र शाजापुर के कुल 17 ग्रामों की 2728 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना से उज्जैन जिले को उद्योग एवं पेयजल हेतु 129.60 एमएलडी जल, नागदा नगर को उद्योग एवं पेयजल हेतु 129.60 एमएलडी जल तथा तराना, घट्टिया एवं गुराडीया गुर्जर को 21.60 एमएलडी जल पेयजल के लिए प्रदाय होगा। परियोजना से शाजापुर जिले के ग्राम समूह तथा शाजापुर नगर के पेयजल के लिए 43.20 एमएलडी और मक्सी में पेयजल एवं उद्योग हेतु 43.20 एमएलडी का जल प्रदाय होगा। परियोजना में ओंकारेश्वर जलाशय से (ग्राम बड़ेल जिला खंडवा) से भूमिगत पाइप लाइन द्वारा 15 घन मी. प्रति सेकेण्ड की दर से जल 435 मीटर ऊंचाई तक कुल 6 पंपिंग स्टेशन एवं 50 पंप मोटर के माध्यम से उद्वहित किया जायेगा। परियोजना में मुख्य पाइप लाइन एवं वितरण प्रणाली से 2.5 हेक्टेयर चक तक कुल 2254 कि.मी. (3000 एमएम व्यास से 63 एमएम व्यास) पाइप लाइन बिछाई गई है। प्रति 20 हेक्टेयर पर एक ओ.एम.एस. बाक्स अर्थात कुल 1539 बॉक्स स्थापित किये गये हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगीः राजपूत

भोपाल (काप्र)।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला स्व-सहायता समूहों/ग्राम संगठकों को कार्य देने का प्रावधान उपार्जन नीति में किया गया है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि महिला स्व-सहायता समूहों/ग्राम संगठकों को उपार्जन कार्य देने के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर निर्देश जारी कर दिये गये हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों/ग्राम संगठकों का एक वर्ष पूर्व (एक जनवरी, 2025 की स्थिति में) का पंजीयन होना चाहिए। महिला स्व-सहायता समूहों/ग्राम संगठकों के बैंक खाते में न्यूनतम 2 लाख रूपये जमा हों। समूह द्वारा विगत एक वर्ष में नियमित रूप से बैठकों का जायोजन किया गया हो। समूह में समस्त सदस्य/पदाधिकारी महिलाएं हो। विगत वर्षों में उपार्जन कार्य में कोई अनियमितता नहीं की गयी हो और महिला स्व-सहायता समूहों/ग्राम संगठकों को उपार्जन कार्य देने के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अनुशंसा जरूरी है। समूहों को पंजीयन प्रमाण-पत्र, विगत 6 माह के बचत खाते का बैंक स्टेटमेंट, विगत 3 माह की बैठकों का कार्यवाही विवरण और आवश्यक राशि की उपलब्धता का प्रमाण सहित अन्य जरूरी दस्तावेज देने होंगे। उपार्जन कार्य के लिए महिला स्व-सहायता समूहों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। महिला स्व-सहायता समूहों/ग्राम संगठकों को उपार्जन कार्य के लिये विभाग द्वारा उपार्जन एवं पंजीयन की अवधि के लिये कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय दिया जायेगा। साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन एवं प्रासंगिक व्यय भी दिये जायेंगे।

अंतरिक्ष परी की वापसी पर खुशी का इजहार

राजधानी में बुधवार को रंगपंचमी के अवसर पर अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष से सकुशल वापस लौटने पर खुशी के रंगों के संग भवानी मंदिर पर लोगों ने उनका पोस्टर लेकर आनंदोत्सव मनाया।

हाईकोर्ट में तलाक मामले की सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

भोपाल (काप्र)। मप्र हाईकोर्ट के न्यायाधीश एमए धर्माधिकारी तथा संजीव एस कालगांवकर की खंडपीठ में तलाक मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील पंकज खंडेलवाल ने खंडपीठ को बताया कि जैन धर्म को हिंदू से अलग नहीं माना जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदुओं की जो व्याख्या की गई है। उसमें सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को शामिल किया गया है।

इस मामले में वरिष्ठ वकील सुनील जैन और रोहित मंगल ने कहा, 2014 में जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। बौद्ध और सिख पहले से ही अल्पसंख्यक हैं। जैन समाज को अल्प संख्यक का दर्जा देने के नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार ने केवल आरक्षण का उल्लेख किया है। संविधान में किसी तरीके का कोई परिवर्तन हिंदुओं की व्याख्या में नहीं किया गया है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश कालगांवकर ने वकीलों से सवाल पूछा, सीआरपीसी इस मामले में क्या कहती है? इस पर उपस्थित वकीलों ने जवाब दिया। निचली कोर्ट कानून के बाहर नहीं जा सकती है। इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। हाई कोर्ट 5 मई को अपना फैसला सुनाएगी। इंदौर की फैमिली कोर्ट ने जैन धर्म के युगलों द्वारा मांगे गए तलाक के मामले में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक देने से इनकार कर दिया था। 28 आवेदनों को खारिज कर दिया गया था। फैमिली कोर्ट का कहना था, जैन धर्म का अपना पर्सनल लॉ है। जैन धर्म के लोगों की हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक मामले की सुनवाई नहीं हो सकती है। फैमिली कोर्ट के जज ने अपने फैसले में कहा था। जैन धर्म के अपने रीति-रिवाज हैं। इसका उल्लेख जैन धर्म के ग्रंथो में है। फैमिली कोर्ट के आदेश के विरोध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

स्पेशल खबर मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वालों का टोटा...

मप्र में कब सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था, कैसे मिलेंगे अच्छे चिकित्सक

भोपाल (काप्र)। मप्र सरकार प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के दावे कर रही है, वहीं प्रदेश में चल रहे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में टीचिंग फैकल्टी के आधे से ज्यादा पदों को अभी तक भरा ही नहीं जा सका। प्रदेश के 19 मेडिकल कॉलेजों में प्राध्यापक से लेकर डोमेस्ट्रेटर के 3660 पदों में से 2100 पदों को ही अभी तक भरा जा सका है।

राज्य सरकार ने यह जानकारी मप्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक के सवाल के जवाब में दी है। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में बताया गया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जहां टीचिंग स्टॉफ की कमी है, वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में स्वीकृत पदों से कहीं ज्यादा स्टॉफ मौजूद है। मप्र में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के दावे कर रही है। अभी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 19 हो गई है। हालांकि पहले से चल रहे मेडिकल कॉलेजों में ही टीचिंग स्टॉफ की पूर्ति नहीं हो पाई है। कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती के सवाल के जवाब में सरकार द्वारा दी गई जानकारी से इसका खुलासा हुआ है। टीचिंग फैकल्टी के मामले में सबसे ज्यादा खराब हालत नए खोले गए मेडिकल कॉलेजों की है। कांग्रेस विधायक ने सवाल पूछा था कि प्रदेश में कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और शासकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और उनमें डॉक्टर्स के स्वीकृत पद और रिक्त पद कितने हैं। जवाब में सरकार ने बताया कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में टीचिंग फैकल्टी के 2118 पद खाली हैं।

सभी कॉलेजों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और प्रदर्शक सहित कुल 3660 पद हैं। इसमें से 2118 पद खाली पड़े हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति नए खोले गए मेडिकल कॉलेजों की है। सतना मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापक के 22 पदों में से सिर्फ 6 भरे हैं। सह प्राध्यापक के 48 में से 16 और सहायक प्राध्यापक के 76 में से सिर्फ 51 को ही भरा जा सका। नीमच मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापक के 22 में से सिर्फ 2 पदों को ही भरा जा सका। इसी तरह सह प्राध्यापक के 40 में से 7 पद और सहायक प्राध्यापक के 56 में से 19 पद पर ही टीचिंग स्टॉफ मिला। जबकि डिमोस्ट्रेटर के लिए 32 पदों में से एक को भी नहीं भरा जा सका। सिवनी मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापक के 22 पदों में से 7 को ही भरा जा सका। सह प्राध्यापक के 40 में से 20, सहायक प्राध्यापक के 56 में से 29 और डिमोस्ट्रेटर के सभी 32 पद खाली हैं। सिंगरौली मेडिकल कॉलेज में तो एक भी प्राध्यापक की नियुक्ति नहीं की जा सकी, जबकि इसके 20 पद हैं। इसी तरह सह प्राध्यापक के भी सभी 40 पद खाली हैं। सहायक प्राध्यापक के 56 में से 6 पद भरे जा सके जबकि डिमोस्ट्रेटर के सभी 32 पद खाली हैं। मंदसौर मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापक के 20 में से 5 पद भरे जा सके। सह प्राध्यापक के 40 में से 12 पद और सहायक प्राध्यापक के 56 में से 23 पदों को भरा जा सका। वहीं डिमॉस्ट्रेटर के सभी 32 पद खाली हैं। श्योपुर मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापक के सभी 22 पद खाली हैं, वहीं सह प्राध्यापक के 40 में से 1 पद और सहायक प्राध्यापक के 56 में से 4 पदों को ही भरा जा सका। इसी तरह डिमोस्ट्रेटर के सभी 32 पद खाली हैं। विदिशा में खोले गए मेडिकल कॉलेज में भी स्टॉफ की कमी है। यहां प्राध्यापक के 22 में से 13, सह प्राध्यापक के 39 में से 31, सहायक प्राध्यापक के 58 में से 38 पद ही भरे जा सके।

पैरामेडिकल स्टॉफ की भी कमी: सरकारी मेडिकल कॉलेजों में टीचिंग स्टॉफ के साथ पैरामेडिकल स्टॉफ की भी कमी है। प्रदेश के 19 मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल स्टॉफ के 3279 पद स्वीकृत हैं, जबकि 1767 पदों को ही अब तक भरा जा सका है। इस तरह 1500 से ज्यादा पैरामेडिकल का स्टॉफ ही नहीं है। एक तरफ प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में टीचिंग स्टॉफ की कमी है तो वहीं प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में टीचिंग स्टॉफ स्वीकृत पद से भी ज्यादा है। प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की संख्या 13 है। इन कॉलेजों में कई जगह स्वीकृत पद से 35 फीसदी तक ज्यादा टीचिंग स्टॉफ मौजूद है।

प्रदेश सरकार बुधनी, मंडला, श्योपुर, सिंगरौली और राजगढ़ में भी नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है। यह सभी कॉलेज 150-150 सीटों के होंगे। उधर विधानसभा में कांग्रेस विधायक के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि प्रदेश में खाली पदों की पूर्ति निरंतर प्रक्रिया है। इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com